



**Saavdhaan! There's A Beast Within!**

I got conned transferring a large sum of money. And when I went to the police, they mocked me, saying 'You make Saavdhan India!'

**Beyond Forts And Palaces**

**Russia, Ukraine and the European Story**

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtrdoot.com

# राष्ट्रदूत

Rashtrdoot

## तृणमूल सरकार का घुसपैठियों को संरक्षण, सुरक्षा से खिलवाड़ है- मोदी

प्रधानमंत्री ने हुगली में विशाल आमसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार को कठघरे में खड़ा किया

कोलकाता/नयी दिल्ली, 18 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि तृणमूल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देकर बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि ये घुसपैठिए उनके लिये पक्का वोट बैंक हैं। मोदी ने रविवार को हुगली में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में अवैध घुसपैठ, कानून-व्यवस्था की बहाली, भ्रष्टाचार और केन्द्र सरकार की योजनाओं को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और इसी सोच के साथ केन्द्र सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने

■ प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ, कानून व्यवस्था की बहाली, भ्रष्टाचार और केन्द्र सरकार की योजनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे जिम्मेदार ठहराया।

■ प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद पिछले 100 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है, जब 24 घंटे के भीतर बंगाल की रेल संरचना को लेकर इतने बड़े फैसले लिए गये हों।

कहा "कल मैं मालदा में था और आज हुगली में आप सभी के बीच हूँ। पिछले 24 घंटे पश्चिम बंगाल के रेल और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ऐतिहासिक रहे हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगूर की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग 15 साल के महा-जंगलराज से मुक्ति चाहते हैं। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

(राजग) ने जंगलराज को रोका, वैसे ही बंगाल अब तृणमूल के महा-जंगलराज को विदा करने के लिए तैयार है।

मोदी ने अवैध घुसपैठ को बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि तृणमूल सरकार घुसपैठियों को खूली छूट दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल घुसपैठियों के समर्थन में धरने-प्रदर्शन तक करती है, क्योंकि वह उनके लिए वोट बैंक है और सरकार को देश तथा बंगाल की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। यह सरकार

घुसपैठियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने बंगाल के युवाओं से विशेष रूप से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी स्तर में स्वीकार नहीं की जा सकती।

मोदी ने बताया कि पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा, बंगाल को करीब आधा दर्जन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं, जिनमें से तीन ट्रेनें आज ही शुरू की गई हैं। इनमें एक ट्रेन उनके संसदीय क्षेत्र काशी को बंगाल से जोड़ने वाली है और अन्य ट्रेनें दिल्ली और तमिलनाडु के लिए चलाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि शायद पिछले 100 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब 24 घंटे के भीतर बंगाल की रेल संरचना को लेकर इतने बड़े फैसले लिए गए हों।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ट्रंप के विरोध में ग्रीनलैंड व डेनमार्क में विशाल विरोध प्रदर्शन

कोपेनहेगन, 18 जनवरी। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के अमेरिकी प्रयासों और बयानों के विरोध में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के कई शहरों में विशाल विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं।

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के सिटी हॉल स्क्वायर पर शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे (भारतीय समयानुसार अपराह्न 4:30 बजे) भारी भीड़ जमा हुई, जिसने अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकाला।

■ ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में हुए प्रदर्शन में प्रधानमंत्री निल्सन भी शामिल हुए।

इस प्रदर्शन में डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों देशों के नागरिक शामिल हुए, जो अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए थे।

इस बीच ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में भी दोपहर से ही लोग जुटना शुरू हो गए और "ग्रीनलैंडवासियों का है ग्रीनलैंड" के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक इटुट गीत गाए और कई लोग "मेक अमेरिका गो अवे" (अमेरिका को वापस भेजो) लिखी हुई टोपियों पहने नजर आये।

## यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर रोक लगाई

अमेरिका द्वारा यूरोपीय यूनियन व डेनमार्क पर आयात शुल्क की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया

ब्रुसेल्स, 18 जनवरी। ग्रीनलैंड मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईयू ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है।

ईयू ने यह कदम डेनमार्क और संघ के कई देशों पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क लगाने की चेतावनी के बाद उठाया है। ईयू के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये आयात शुल्क संघ और अमेरिका के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही, उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ऐसे सिद्धांत हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि जुलाई 2025 में प्रस्तावित समझौते को आयात शुल्क कम करने और टिपिकीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप के रुख और आयात शुल्क लगाने की उनकी चेतावनी के बाद संघ ने इस प्रस्तावित समझौते के अनुमोदन को रोकने का आ आ किया है।

■ ईयू के नेताओं ने डेनमार्क व ग्रीनलैंड को पूर्ण समर्थन दोहराते हुए कहा कि संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता ऐसे सिद्धांत हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

ट्रंप ने ग्रीनलैंड के रणनीतिक स्थान और खनिज संसाधनों को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी, "एक फरवरी 2026 से, उपयुक्त सभी देशों द्वारा अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। एक जून 2026 को यह शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा, जब तक ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए कोई समझौता नहीं हो जाता।"

यूरोपियन पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष सिगफ्राइड मूरसन और अन्य यूरोपीय अधिकारियों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घोषणा उस स्थिरता को कमजोर करती है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए यह व्यापार समझौता किया गया था।

मूरसन ने कहा, "पिछले साल

अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हुए व्यापार समझौते से स्थिरता ही एकमात्र लाभ होता। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई ईयू सदस्य देशों पर नए आयात लगाने की आज की घोषणा उस स्थिरता को छीन लेती है। यही कारण है कि उस व्यापार समझौते के अनुसमर्थन को स्थगित करना उचित है।"

मूरसन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम पिछले जुलाई के ईयू-यूएस व्यापार समझौते को बहुत जल्द अनुमोदित करना था, जिससे अमेरिका से यूरोपीय संघ में होने वाले आयात पर आयात शुल्क शून्य हो जाता। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए इस मंजूरी के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।"

अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए डेनमार्क के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## धर्म ही मुझे और नरेन्द्र मोदी को चला रहा है- भागवत

संघ प्रमुख ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित किया

मुंबई, 18 जनवरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आरएसएस के कार्यक्रम में अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा कि धर्म ही मुझे और नरेन्द्र मोदी को चला रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म पूरे ब्रह्मांड का चालक है। जब सृष्टि अस्तित्व में आई, तो उसके कामकाज को नियंत्रण करने वाले नियम धर्म बन गए। सब कुछ उसी सिद्धांत पर चलता है।

आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश को सदैव संतों और ऋषियों से मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब तक ऐसा धर्म भारत को चलाएगा, वह विश्वगुरु बना रहेगा। मोहन भागवत ने धर्म को

■ मोहन भागवत ने कहा कि देश को सदैव संतों व ऋषियों का मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब तक ऐसा धर्म भारत को चलायेगा, वह विश्व गुरु बना रहेगा।

केवल पूजा-पाठ तक सीमित न मानते हुए कहा कि प्रकृति की हर वस्तु में कर्तव्य और अनुशासन निहित है। सृष्टि बनने के बाद उसके संचालन के नियम ही धर्म बने और सब कुछ उसी नियमों पर चलता है। दुनिया में आध्यात्मिकता की कमी है, इसलिए ऐसा ज्ञान वहां नहीं मिलता। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति या रचना धर्म के बिना नहीं हो सकती।

जाति व्यवस्था पर चर्चा करते हुए भागवत ने कहा कि इसे समाप्त करने के लिए मन से जाति की भावना को मिटाना आवश्यक है। पहले जाति काम और पेशे से जुड़ी थी, लेकिन

बाद में यह भेदभाव का कारण बन गई।

भागवत ने आरएसएस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन का लक्ष्य समाज के साथ मिलकर भारत को उसके सर्वोच्च गौरव तक पहुंचाना है।

संघ व्यक्ति के चरित्र निर्माण के जरिए राष्ट्र निर्माण करता है। उन्होंने साफ किया कि आरएसएस किसी से बाद मेयर पद की जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है।

संघ खुद बड़ा नहीं बनना चाहता, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। जो लोग संघ को समझना चाहते हैं, उन्हें उसकी शाखाओं में आना चाहिए।

## कोई नहीं चाहता, मुंबई में भाजपा का मेयर बने- राउत

मुंबई, 18 जनवरी। बीएसपी चुनाव के नतीजे आने के बाद मुंबई की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना-यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि शिंदे गुट ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के ताज

■ संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिंदे ने 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में बंधक बना रखा है।

होटल में बंधक बनाकर रखा है। राउत के इस बयान ने नगर निगम चुनाव के बाद मेयर पद की जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है।

संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतकर आए पार्षदों को होटल में कैद कर दिया गया है। राउत ने कहा, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## शिंदे ने मुंबई के महापौर पद पर दावा किया, भाजपा नाराज़

चर्चा के अनुसार, यह विवाद कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में वर्चस्व से भी जुड़ा हुआ है

मुंबई, 18 जनवरी। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति गठबंधन के भीतर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा मुंबई महानगरपालिका के महापौर और स्थायी समिति अध्यक्ष पद पर दावे किए जाने से भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है।

सूत्र बताते हैं कि भाजपा नेताओं का मानना है कि मुंबई की जनता ने महायुति पर भरोसा जताया है, लेकिन ऐसे समय में सहयोगी दल द्वारा दबाव की राजनीति अच्छे संकेत नहीं देती। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं ने अपनी यह नाराजगी सीधे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के सामने रखी है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह पूरा विवाद केवल मुंबई के पदों की लड़ाई नहीं है, बल्कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) में

■ केडीएमसी शिंदे के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ के नगर निगम में शिंदे को भाजपा से एक सीट अधिक प्राप्त हुई है।

की राजनीति से भी जुड़ सकता है। कुछ सूत्रों का दावा है कि शिंदे गुट, जो केडीएमसी में भाजपा से सिर्फ एक सीट आगे है, अब अप्रत्यक्ष दबाव बनाकर गठबंधन के भीतर अधिक पद हासिल करने की रणनीति अपना रहा है।

शुक्रवार को घोषित अंतिम नतीजों में 122 सीटों वाली केडीएमसी में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 52 सीटें, जबकि भाजपा ने 51 सीटें जीतीं। यानी शिंदे गुट मात्र एक सीट से आगे रहा। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) को केवल 11 सीटें, एमएमएस को 5, कांग्रेस को 2 और एनसीपी (शरद पवार) को 1 सीट

मिली। विश्लेषकों का कहना है कि शिंदे के लिए केडीएमसी राजनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यह उनका गढ़ माना जाता है, जबकि मुंबई में भाजपा की मजबूत पकड़ है। ऐसे में दोनों नगर निगमों में सहयोग के बिना सरकार गठन और सत्ता संतुलन मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि शिंदे गुट अब अधिक निगोशिएशन पावर दिखाने की कोशिश में है, जबकि भाजपा इसे दबाव की राजनीति मानकर नाखुश है। गठबंधन के दोनों दलों को एक-दूसरे की जरूरत है, विशेषकर मुंबई और केडीएमसी दोनों ही जगहों पर।

## संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति आज दिल्ली आएंगे

नयी दिल्ली, 18 जनवरी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। शेख नाहयान की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर हो

■ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत उर्जा साझेदारी है, जिसमें दीर्घकालीन उर्जा आपूर्ति व्यवस्था शामिल है।

रही है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद उनकी भारत की यह तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी, और पिछले एक दशक में यह उनकी भारत की पाँचवीं यात्रा होगी। यह यात्रा हाल ही में हुए उच्च-स्तरीय आदान- (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पूर्णतया डॉलर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता भारत

इस पूर्ण निर्भरता का दुष्परिणाम भारत के सामने है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध ने रूस को विदेशी मुद्रा के रिज़र्व्स को ब्रेफ्रीज कर दिया था

—सुकुमार साह—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 जनवरी। जैसे-जैसे ग्लोबल फाइनेंस एक तेजी से विवादित जियोपॉलिटिकल एरिया बनता जा रहा है, भारत सावधानी से खुद को एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ रहा है, जो समय के अनुसार, यू.एस. डॉलर के साथ सीधा टकराव किए बिना, उसके दबदबे को कम कर सकता है। यह पहल, जिसे ब्रिक्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, एक नया डिजिटल पैमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है जिसे वेस्टर्न कंट्रोल वाले फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क और डॉलर-बेस्ड कार्रैसैडेंट बैंकिंग सिस्टम पर निर्भरता

■ भारत ने डॉलर पर पूर्ण निर्भरता से बचने के लिए "ब्रिक्स ब्रिज" सिस्टम शुरू किया है। "ब्रिक्स ब्रिज" के मार्फत नए विकाशशील देश, माला निर्यात-आयात का सेंटलमेंट अपनी स्वयं की मुद्रा से कर सकेंगे।

■ यह नया "ब्रिक्स ब्रिज" सिस्टम भारत के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत अपनी ऑयल की खपत का 80 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है तथा रूस से भी पुराने व मजबूत सामरिक संबंध रखता है। अतः यूरोपियन द्वारा सीधे रूस से ऑयल खरीद पर प्रतिबंध लगाने पर, भारत ने वैकल्पिक पैमेंट की व्यवस्था का इस्तेमाल किया।

■ भारत यह "इम्पेशन" भी नहीं देना चाहता कि वह डॉलर विरोधी है, पर सारे निर्यात-आयात के लिए केवल एक "गेट कीपर" पर ही निर्भर रहना नहीं चाहता। इसलिए भारत "ब्रिक्स ब्रिज" सिस्टम को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत यह जानता है कि "ब्रिक्स ब्रिज" सिस्टम पूर्णतया विकसित होने में काफी समय लगेगा, तब तक भारत डॉलर विरोधी होने की छवि भी नहीं ओढ़ना चाहता, जिससे वह अमेरिका का कोप-भाजन बने।

कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट करता है। नई दिल्ली के लिए, इस प्रोजेक्ट का महत्व डॉलर को सीधे चुनौती देने

में नहीं है, बल्कि भविष्य में अलग-अलग रास्ते चुनने की रणनीतिक आज्ञादी में है, जब एक समानांतर वित्तीय रास्ता बनाने के बारे में है, जिससे

भारत को ट्रेड, एनर्जी खरीद और क्रॉस-बॉर्डर धुगतानों में ज्यादा स्वायत्तता मिले, ऐसे समय में है। यू.ए. जियोपॉलिटिक्स फाइनेंस तक पहुंच को

तेजी से आकार दे रही है। भारत कभी भी वैचारिक रूप से डॉलर का विरोधी नहीं रहा है। यू.ए. करेंसी भारत के ट्रेड इनवॉइसिंग, फॉरेन

कैपिटल इनफ्लो और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में केन्द्रीय भूमिका निभाती है, लेकिन हाल की वैश्विक घटनाओं ने यह दिखा दिया है कि एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था पर अत्याधिक निर्भरता कितनी जोखिम भरी हो सकती है, जहाँ देश के बाहर लिए गए पोलिटिकल फैसलों से एक्ससेस को रोका जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को फ्रीज करने और स्विफ्ट से रूसी बैंकों को कुछ हद तक बाहर करने से भारत बहुत मैसेज गया। इस घटना ने दिखाया कि कैसे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार बनाया जा सकता है, और कैसे बड़ी इकॉनमी भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ यह बोर्ड गाज़ा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है।

प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। भारत को यह न्योता उसकी वैश्विक साक्ष, संतुलित विदेश नीति और शांति प्रयासों में भूमिका को देखते हुए दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बोर्ड में शामिल देश गाजा की स्थिति पर नजर रखेंगे, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और संघर्ष रोकने से जुड़े कदमों पर विचार करेंगे। हालांकि, इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ट्रंप ने गाज़ा "बोर्ड ऑफ पीस" के लिए भारत को आमंत्रित किया

वॉशिंगटन, 18 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाज़ा में शांति बहाली के लिए बनाए जा रहे "बोर्ड ऑफ पीस" का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड गाज़ा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति